

NT>

Title: Need to include left out villages for construction of link roads under Pradhan Mantri Gramin Sarak Yojna particularly in Jalesar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

प्रो. एस.पी.सिंह बघेल (जलेसर) : प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो केन्द्र सरकार की योजना है, जिसमें नियम है कि यदि किसी गांव की आबादी 1000 से अधिक है और वह कहीं से किसी भी सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो इस योजना में सड़क बनेगी। सम्पूर्ण देश में उ.प्र. में मेरे लोक सभा क्षेत्र जलेसर में पी.एम.जी.एस.वाई. में फेज-1, फेज-2 एवम् फेज-3 बन चुकी है। अंतिम उद्देश्य 2007 तक 250 से 500 तक की आबादी के गांव को सड़क से जोड़ना है। राज्य सरकारों द्वारा जिले का मास्टर प्लान बनाते समय भौतिक सत्यापन न करने के कारण इस योजना की शर्तों को पूरा करने के बाद भी बहुत से गांव कार्य योजना बनाते समय छूट गए हैं जो विकास से वंचित रह जाएंगे। मेरे लोक सभा क्षेत्र के टूंडला जिला फिरोजाबाद के गांव नगलाछैकुर, रामपुर, पखरपुरा, हरचन्दपुर, नारखी ब्लाक के गांव भरतपुरा, नगला, गड़रिया गढ़ी, अहिवरन, फिरोजाबाद ब्लाक के गांव सदासुख तथा जलेसर (जिला एटा) ब्लाक के गांव नगवाई, नगला मीरा, फाजिलपुर, क्यार, अवागढ़ ब्लाक के गांव दुपरिहा, बलीदादपुर, नारऊ, मदेसरा, नगला उदई तथा सादाबाद ब्लाक जिला हाथरस के गांव फत्ता का नगला, विधिपुर तथा ब्लाक सहपऊ के गांव नगला ब्राह्मण तथा इसी प्रकार निधौली कलां एवम् मारहरा ब्लाक जिला एटा के प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सभी अहर्ताएं पूर्ण करने के बाद वंचित रह गए। कृपया राज्य सरकारों को निर्देशित करें कि प्रत्येक गांव का भौतिक सत्यापन पुनः करके छूटे हुए गांवों को पूरे देश में समाहित करें तथा मेरे लोक सभा क्षेत्र के छूटे हुए गांवों को अविलम्ब शामिल करने का निर्देश देने का कट करें तथा इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का शिलान्यास सांसदों से कराने का निर्देश भी राज्य सरकारों को भेजने का कट करें।